

एक नजर

व्यापारी का अपहरण,
हत्या की धमकी

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। एक नौजवान व्यापारी के अपहरण की बात सामने आई है। अपहरण के बाद हत्यादरमप घंट पर जान-माल की चीजों की देने का मामला सामने आया तो परिजनो सहित पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हत्यादरमप पर मिली धमकी में व्यापारी के भाई को संबोधित करते हुए लिखा है कि कहीं शिकायत की तो तुम्हारे भाई की लाश मिलेगी। मामला गौर थाना क्षेत्र का है। पुलिस और एसओजी अग्रदूत व्यापारी की तलाश में जुट गई है।

रविवार की देर रात गौर थानाक्षेत्र के परसखीह गांव निवासी बबलू करंजीन ने पुलिस को सूचना दी कि गौर स्टेशन के पीछे उसका भाई अजय करंजीन का प्रयास कर रहा है लेकिन तुम्हारा भाई हर बार बीच में आ जाता था। आज तुम्हारे भाई का अपहरण कर लिया है। फोन पर सम्पर्क मत करो क्योंकि वह अभी बेहोश है। कहीं शिकायत की तो तुम्हारे भाई की लाश ही मिलेगी। हत्यादरमप घंट पर मिली धमकी से परिजनो के हाथ पांव फूल गए। परिहार में कोहराम मच गया। इसकी सूचना पुलिस महकमे को दी गई तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। एसओजी, सर्विलांस सहित गौर पुलिस हरकत में आई और सर्वािलांस सेल की मदद से पतावर छाक छानती रही। इस बाद प्रभारी निरीक्षक गौर राम कुमार राजवार ने बताया कि पीछित के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

बोलोरो को लेकर
चम्पत हो गए चोर

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। सोनहा बाजार में घर के सामने खड़ी बोलोरो पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मुख्य बाजार में हुई इस घटना से स्थानीय व्यापारियों में रोष है। सूचना पर सीमावर्ती की सुबह घटनास्थल पर पहुंची सोनहा पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। सोनहा थानाक्षेत्र के कमरिया बाजार निवासी दीनानाथ पांडेय पुत्र बंजरका जगन्नाथ ने सोनहा बाजार में मगान बना रखा है। मकान के अंदर हिस्से में उन्होंने बकरी की दुकान खोल रखी है। दीनानाथ के अनुसार रविवार की रात दुकान बंद होने के बाद बोलोरो रोज की तरफ मकान के दरवाजे पर ही खड़ी थी। सोमवार की सुबह जब उठे तो देखा कि बोलोरो वहां नहीं खड़ी थी। तत्काल सूचना डायल 112 पर दी। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंच गई। अपहरण की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस चोरी की घटना का सुराग लगाने में जुटी है।

जमीन हड़पने के मामले में
कोर्ट के आदेश पर मुकदमा

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। हरैया पुलिस ने घोषणा की है आरोप में कोर्ट के आदेश पर सात लोगों पर केस दर्ज किया है। छावनी थाने के जीजीरामपुर निवासी ओकर मिश्र ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि विपक्षियों ने जमीन हड़पने के उद्देश्य से एक फर्जी निष्पक्ष तैयार कर बलिकरन की घटना केनोना में स्थित समूहों जमीन राजस्व अभिलेख में गलत तरीके से नाम दर्ज करा दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पुनर्जांच करा दी। यही, श्याम, सुभाषचंद्र दास, रवी, दीप, श्याम, सुभाषचंद्र दास, रवी, दीप निवासी जमीनराजपुर, लाठी देवी निवासी परसरामपुर और राममूल निवासी अमीनीहरी थाना हरमूल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

3 खालिस्तानी आतंकी पुलिस मुठभेड़ में ढेर: असलहे बरामद

पौलीभौत (आमा)। पौलीभौत में तीनों आतंकी खालिस्तानी कमांडो फोर्स के सदस्य बताए जा रहे हैं। उनके पास से दो एके-47 गन और दो

चौधरी चरण सिंह ने किसान हितों के लिये आखिरी सांस तक संघर्ष किया- अरुणेंद्र पटेल



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को उनकी जयन्ती पर पर किसान दिवस के रूप में याद किया गया। सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने रूखली विमानसमायक रामकुमार चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद भागपुर तहसील के सामने आयोजित संगोष्ठी और सहभोज में चौधरी चरण सिंह के योगदान पर चर्चा किया।

रालोद के प्रदेश महासचिव अरुणेंद्र पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को सम्मोहित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह एक समर्पित सार्वजनिक कार्यकर्ता और सामाजिक न्याय में दृढ़ विश्वास रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने किसान हितों के लिये आखिरी सांस तक संघर्ष किया। प्रगल्भता के रूप में उन्होंने किसानों के लिये जो नीतियां बनायीं उसका लाभ आज तक किसानों को मिल रहा है। रालोद उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिये निरंतर प्रयासशील है। संकाल करती हुये सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि आगे का रास्ता शुभिल रहें।

लेखपाल पर ग्राम प्रधान और ग्रामीणों का फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। सोमवार को विकास खण्ड बस्ती सदर के ग्राम पंचायत मुझडीहा के नगरपाली में विक्रम गौतम, हरिकेश गौतम के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्रामसभा मुझडीहा में आवसीय पट्टा के आंतरद हेतु ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्ताव बनाकर कागज गो को दिया गया था। इस पर हल्का लेखपाल रितेश शुक्ला ने पूर्व ग्राम प्रा. जा कुलदीप, और मंजु का फर्जी हस्ताक्षर बनाया लिगा। यही नहीं लेखपाल ने ग्राम प्रधान की फर्जी मोहर और हस्ताक्षर बनाया लिगा। इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधान महेश ने भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर लेखपाल



रलीक पिस्टल के अलावा भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं। मारे गए आतंकीयों की पहचान गुरविंदर सिंह, रवि और जसप्रीत के रूप में हुई है। तीनों पर 18 दिसम्बर को पंजाब के गुरदासपुर पुलिस चौकी पर हुए घनेड हमले में शामिल रहने का आरोप था। सोमवार की सुबह पौलीभौत से आई एकाउण्टर को इस खबर को सूची और पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यह एकाउण्टर पौलीभौत के पूरनपुर इलाके में हुआ है। पंजाब पुलिस की एक टीम तीनों

भाकियू ने किया चौधरी चरण सिंह को नमन: किसान समस्याओं पर व्यापक चर्चा



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। भारतीय किसान यूनियन द्वारा सोमवार को पूरनपुर अख्यक अणु कुमार चौधरी के संयोजन में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के याद किया गया। सिताई डाक बंगले के परिसर में स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद आयोजित संगोष्ठी में बक्ताओं ने कहा कि देश का किसान सबसे बुरे दर्जे में गुजर रहा है। इसलिये एकाउण्टर होकर संघर्ष करते हुये अधिकार हासिल करने होंगे, यही चौधरी चरण सिंह के प्रतीक श्रद्धांजलि लिगी।

गौरी को भाकियू के प्रदेश सचिव दिवान चन्द पटेल, जयराज वर्मा, शोभाकर ठाकुर, जिलाध्यक्ष गौरीचंद चौधरी, गनीराम, विनोद कुमार, विवेनी चौधरी आदि ने संबोधित ता किया।

संयोजन के अन्तर्गत न्यूतम शक्ति सम्मेलन के अन्तर्गत, स्वामीनाथन हरे पेड़ों की अवैध कटान रोकने की मांग



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। दुबौलिया थाना क्षेत्र की हरियालपुर निवासिनी राजपुत्री देवी पत्नी अनुरुद्ध ने जिलाधिकारी को प्रधाना पत्र देकर ग्रामसभा के

विद्यार्थियों की शूलक प्रतिप्रतिन न होने तथा कक्षा 9 व 11के परीकरण सुचारु का निमित्त और न मिलने से हर विद्यार्थी आर्थिक संकट भेल रहने से हर विद्यार्थी अख्यक अणु कुमार चौधरी को भाकियू के प्रदेश सचिव दिवान चन्द पटेल, जयराज वर्मा, शोभाकर ठाकुर, जिलाध्यक्ष गौरीचंद चौधरी, गनीराम, विनोद कुमार, विवेनी चौधरी आदि ने संबोधित ता किया।

अन्य संघर्षों की तरह विस्त्रीय वेतनमान की सुविधा दी जाय। धरने में संयोजक डा धनरथ्याम श्रीवास्तव,संयोजन मंत्री रामप्रीत यादव, संयोजन मंत्री चन्द्रनाथ कौशिक पाण्डेय, सदस्य संघर्ष समिति सतीश रंजन सिंह, दिनेश वर्मा, संयुक्त मंत्री कुपु विजय यादव, विजय कुमार,कोरलेश कुमार मिश्र,विजय शंकर सिंह,अशोक कुमार पाण्डेय,पुनल किशोर मिश्र,उज्जैन प्रभास सिंह, विनोद प्रकाश वर्मा,सर्वेन्द्र कुमार,वीरेंद्र सिंह उपजित राम वर्मा,कुपु गिर, कुमार शर्मा,सुनील कुमार, पाण्डेय,शामभद्र राम बबन,विजय राम निपाटी,राजमन्धन मिश्र ने भाग लिया। धरना के अंत में ज्ञापन प्राप्त करने के बाद जिला विधानसभा निरीक्षक ने स्थानीय समस्याओं के यथाशीघ्र समापन को, और 14 सूचीय ज्ञापन को तत्काल मुख्यमंत्री महोदय तक प्रेषित करने का आश्वासन दिया।

पुलिस की लापरवाही से आहत किशोरे ने फांसी लगाकर जान दिया

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। कप्तानगंज पुलिस की कार्यशील से आहत होकर एक 15 वर्षीय किशोरे ने अपनी जान दे दी। आरोप है कि नहिहाल के कुछ युवकों ने उसके कपड़े उतार और उसका अस्सील वीडियो बना लिया था। इसकी शिकायत जब पुलिस से की गई तो पुलिस को आरोपितों को पकड़कर थाने ले आई। बाद में इन दोनों को छोड़ दिया गया। सोमवार को दिन में किशोरे के फांसी लगाने की सूचना मिलते ही सनसनी फैल गई। परिजन शव लेकर कप्तानगंज थाने पहुंच गए। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कारंवाई की मांग की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजना बाधा तोड़कर कर दिया। यहां से शव लेकर परिजन एसपी कार्यालय चले गए और वहां भी मुकदमा दर्ज होने व निष्पत्ती होने के बाद ही पोस्टमार्टम करवा जाने की मांग पर डटे हैं। पुलिस अक्सर परिजनो को समझाने में जुटे हैं।



रात्रि पर लौट आया था। आरोप है कि उसे गांव के एक लड़के ने फांसी कर बुलाया और शराब के नशे में 6 जू लड़कों ने उसके कपड़ा उतार कर पिटाई की और उसका अस्सील वीडियो बना लिया। सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी। मामा ने जानकारी होने पर शिकायत पुलिस से की थी।

पुलिस दो आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले आई और बाद में छोड़ दिया। सोमवार की दिन में इस घटनाक्रम से आहत किशोरे ने नहिहाल में फांसी लगाकर जान दे दी। एसएचओ कप्तानगंज दीपक दुबे का कहना है कि घटना की जांच कर उचित कारंवाई की जा रही है। दूसरी तरफ परिजन सोमवार की शाम तक एसपी कार्यालय पर मुकदमा दर्ज कर निरपत्ता की मांग पर डटे रहे।

मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष बने जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम नई दिल्ली (आमा)। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनएचआर की पूर्व अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार

समाजवादियों ने जयन्ती पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किया नमन

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किसान दिवस के रूप में उनकी जयन्ती पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सोमवार को सजा जिला खस पैतरी सदर विकास महेंद्रनाथ यादव के संयोजन में याद किया गया।



चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण के बाद गौरी को सम्मोहित तो करे हुये विकास महेंद्रनाथ यादव ने कहा कि किसानों के मसीहा के रूप में लोकप्रिय चौधरीचरण सिंह को ऐसे समय पर याद किया जा रहा है जब देश के किसान नीरकार समस्याओं से विरा है, उनकी आवाज को अनसुनी किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह सदैव किसान हितों के लिये संघर्ष करते रहे। उन्हें खूबी श्रद्धांजलि यही होगा कि किसान समूह हों और उनकी मांगों को तत्परता से निराकरण कराया जाय। किसान राजेंद्र चौधरी, कनिष्ठ चौधरी आदि ने कहा कि आज जब किसानों का प्रयोग, गौराहा हमले हो रहे हैं, अविभक्ति की स्वतंत्रता, संविधान पर खरारे हैं ऐसे में हमें चौधरी चरण सिंह से प्रेरणा लेनी होगी जिन्होंने किसान हितों के लिये आखिरी संघर्ष करने के साथ ही उनकी आवाज बने।

पूर्व किसानक रामगण पाण्डेय, सपा के सचिव नेता चन्द्रमुरम मिश्र, दयाशंकर मिश्र आदि ने कहा कि किसान चरण सिंह को अपना मसीहा मानते हैं, उन्होंने कृषकों के कल्याण के लिए कृषकों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। ऐसे नेता विरले होते हैं जिन्हें किसानों का विश्वास हासिल होता है। चौधरी चरण सिंह ने किसान हितों के लिये जो कार्य किया, उन्हें सदैव याद किया जायेगा। कहा कि चौधरी चरण सिंह सच्चे अर्थ में किसानों की मुखर आवाज हैं। जावेद पिचवारी, मो स्याहल, राज सिंह यादव, गुलाब सोनकर, दुर्गास आह, मो. सलीम, अविन्द यादव ने कहा कि नयी पीढ़ी को चौधरी चरण सिंह के संघर्ष और योगदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। कहा कि देश को चौधरीचरण सिंह जैसे नेताओं की जरूरत है। देश और

एचआईवी प्रस्त बच्चों की सेवा के लिये आगे आयी संस्थाओं गोद लेकर किया शिक्षण सामग्री, ऊनी वस्त्र का वितरण



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्त नियंत्रण सोसाइटी द्वारा जिला शिक्षा विभाग बस्ती में संचालित एंटीएडवाइजल क्षेत्री, की एक नई पहल पर स्वयं सेवी संस्था ग्रामीण विकास सेवा समिति और उन्मीद संस्था द्वारा एचआईवी के साथ जीनन यमन कर रहे बच्चों गोद लेकर शिक्षण सामग्री एवं उंड से बचाव उद्देश्य वस्त्र वितरित किया गया। एंटीएडवाइजल क्षेत्री के नौडल अधिकारी डॉक्टर महेश प्रसाद ने कहा कि शिक्षा में एचआईवी के मामले में कृनी शिक्षा के उद्देश्य से स्वास्थ्य शिक्षण एवं सुवीर्यक की विभिन्न इकाइयों योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं, साथ ही ग्रामीण विकास सेवा समिति एवं उन्मीद संस्था के इस बेहतर प्रयास की सहजना करते हुये बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुये शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इन विभाग के अन्य अधिकारियों से वार्ता करे और अन्य वक्ता हम बच्चों को गोद लेने का प्रस्ताव रखते जिससे उनसे दिनचर्या में वृद्धि होगी और बेहतर जीवन जी सकेंगे। कार्यक्रम को संचालित कर रही काउंसलर ज्योत्सना गुप्ता ने अनाथ

के कार्यका के जून में खाम हो जाने के बाद पद खाली था। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने मानवाधिकार संरक्षण आयोग 1993 के तहत जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम को एनएचआर की अध्यक्ष नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश का किसान घोर संकट का सामना कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को नमन करने वालों में मुख्य रूप से निरामन चौधरी, राम उजागर वर्मा, महेंद्र, इरराधन अहमद, राम सुरेश यादव, अमिश जात, देवनाथ यादव, मोला पाण्डेय, चन्द्र प्रकाश चौधरी, प्रभास यादव, संजय गौतम, दिनेश तिवारी, अशोक यादव, राहुल यादव, चन्द्र प्रकाश चौधरी, सीता, प्रकाश वर्मा, वृष्णी यादव, वीरना सुन्दर यादव, विश्वराम चौधरी, दीपक यादव, पवन मोहनयादव, जसवी यादव, जहीर अहमद, जयराज यादव, कुलचन्द भारती, जितेन्द्र यादव, रिंकी सिंह यरुन यादव, पंकज निषाद आदि शामिल रहे। रोगियों की मौत का सबसे बड़ा कारण टीबी है। बताया की विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से एचआईवी संतर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने रॉन सीएफ कर्मीयाय एव दिशा मुनिट के सीपीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि एचआईवी प्रिस्त मरीजों को नियमित रूप से पीछे आहत का सेसन करना चाहिए जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी और वह अनाथ बेहतर जीवन यमन कर सकते हैं। कार्यक्रम में एचआईटी सेलर से अर्चना श्रीवास्तव, श्रवण पाण्डेय, सुनील गुप्ता, नीश मिश्र, अलोक कुमार लाल, सुभा श्रीवास्तव, जिलाधिकारी के मोहम्मद अशरफ, प्रिया पाले, देवा कंकर, सुभा संस्था अरुका मिश्र, मनीष तिवारी, सिमरी एव सीएससी से अजय, अरुणेंद्र आदि ने सभागिता की।

"युद्धो अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक

भारतीय बस्ती

बस्ती 24 दिसम्बर 2024 मंगलवार

सम्पादकीय

चुनाव नियमों में बदलाव

केंद्र सरकार ने चुनाव के कई नियमों में बदलाव कर दिए हैं। निर्वाचन आयोग (ईसी) की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे गए 'कागजात' या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया है। इसे लेकर अब विपक्षी दलों ने केंद्र पर हमला बोला है। जहां कांग्रेस ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को लेकर सवाल उठाया है, वहीं लेफ्ट से लेकर आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र के इस फैसले को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद मामले में कई सवाल उत्पन्न लगे हैं। मसलन—आखिर चुनाव आयोग ने किन नियमों को बदला है और अब किन दस्तावेजों को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए नहीं रखा जाएगा? इसके अलावा इन नियमों को किस आधार पर बदला गया? हाल ही में केंद्र सरकार ने चुनाव नियमों में बदलाव करते हुए सीसीटीवी कैमरा,वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कतिपय इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग की सिफारिशों पर यह कदम उठाया गया। चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93 में यह संशोधन किया गया। दलील दी गई कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का दुरुपयोग रोकने के लिये यह कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव संबंधी रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने के लिये वकील महमूद प्रसाद ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायी थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित आदेशक दस्तावेजों की प्रतियां याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराने को कहा था। दरअसल, प्रधा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव संचालन से संबंधित वीडियोफॉर्म, सीसीटीवी कैमरा फुटेज और फॉर्म 17—सी की प्रतियों की मांग याचिका को जरूरी की थी। हालांकि, चुनाव एजेंट की नियुक्ति, नामांकन फार्म, परिणाम व चुनाव खता विवरण जैसे दस्तावेजों का उल्लेख चुनाव संचालन नियमों में किया गया है। मगर दूसरी ओर आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान सीसीटीवी कैमरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज इसके दायरे में नहीं आते। सरकार के द्वारा हालिया संशोधन इस बात की पुष्टि करता है कि केवल नियमों में उल्लेखित कागजात ही सार्वजनिक निरीक्षण के लिये उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर पारदर्शिता की अवहेलना का आरोप लगाया है। साथ ही सरकार के फैसले को चुनौती देने की बात कही है।

दरअसल, चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि मतदान केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के दुरुपयोग से मतदान की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। दलील दी गई है कि इस फुटेज का इस्तेमाल एआई का उपयोग करके फर्जी विमर्श गढ़ने के लिये किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि लोकतांत्रिक शुचित्ता के लिये पारदर्शिता को क्यों नजरअंदाज किया जाना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीवंतता इसी बात में है कि नागरिकों के सूचना अधिकार का अतिक्रमण किसी भी तरह से न हो सके। निस्संदेह, इस चिंता से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिये तथ्यों से खिलवाड़ संभव है। बहुत संभव है अपनी सुविधा के लिये कतिपय राजनीतिक दल नये विमर्श गढ़ सकें। लेकिन इसके बावजूद आम नागरिकों को उस चुनावी प्रक्रिया को जानने का हक है जिसके जरिये सरकार बनती है। निस्संदेह, किसी भी लोकतंत्र की विश्वसनीयता उसकी पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर करती है। कतिपय सुरक्षा चिंताओं के नाम पर पारदर्शिता का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की मांगों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सजग—सतर्क विपक्ष लोकतंत्र की सफलता के लिये अनिवार्य शर्त भी है। ऐसे में एआई के खतरे के नाम पर हर सूचना के अधिकार पर पहरा नहीं बैठाया जा सकता। वहीं ऐसे निर्णयों में विपक्ष की भागीदारी जरूरी है ताकि सत्तारूढ़ दल पर निरंकुश व्यवहार का आरोप न लग सके।

वैश्विक व्यापार में भारत की बदलती भूमिका



—सुरेश सेठ—

भारत अपनी मुद्रा के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले निरंतर गिरावट को लेकर चिंतित है। इस समस्या से निपटने के लिए ब्रिक्स सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया कि तीसरी दुनिया के देशों और रूस के साथ व्यापार अपनी-अपनी मुद्राओं में किया जाए या डॉलर के बजाय एक वैश्विक मुद्रा का उपयोग किया जाए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि डॉलर के मुकाबले वैश्विक मुद्रा की कोशिशों पर सी प्रतिशत टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा, जिससे व्यापार प्रभावित हो सकता है। फिलहाल, भारत को अपनी आयात-आयात अर्थव्यवस्था को बदलकर निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने की आवश्यकता है, और निवेश आकर्षित करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि वैश्विक निवेश भारत की ओर आकर्षित हो सके।

अमेरिका वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है, जबकि भारत की हिस्सेदारी केवल 1 प्रतिशत है। भारत को अधिकांश सामान जैसे कच्चा तेल और फार्मा उद्योग के



—अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार गिरावट थामाना जरूरी है। विदेशी व्यापार घाटा कम करके यह संभव है यानी निर्यात बढ़ाएं और आयात वृद्धि रोकें। बेशक ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करना, एफटीए व नवाचार जैसे उपाय इसमें कारगर हैं। वहीं आर्थिकी के विभिन्न सेक्टरों को निर्यात प्रतिस्पर्धी भी बनाना होगा।

लिए आवश्यक सामग्री आयात करनी पड़ती है। दरअसल, हम अमेरिका और चीन पर अत्यधिक निर्भर हैं, हालांकि चीन के उत्पादों के निर्यात कम करने की कोशिशों के बावजूद व्यापारिक निर्यात कम नहीं हुई है। भारत को आत्मनिर्भर बनकर आयात को कम करने और निर्यात बढ़ाने की दिशा में जल्दी कदम उठाने की

आवश्यकता है, लेकिन पिछले साल निर्यात वृद्धि बहुत कम रही और आयात की निरंतरता बनी रही। भारत ने आशा व्यक्त की थी कि कोविड महामारी के बाद चीन की कमजोर स्थिति के चलते वह विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकेगा। ट्रम्प ने चीन से आयात पर अतिरिक्त शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी, और

कनाडा, मैक्सिको से भी आयात पर शुल्क लगाया गया था, जबकि हाल ही में चेतावनी को छोड़ दे तो भारत के निर्यात बड़े स्तर पर ऐसा कदम शायद ही उठाया गया हो। चीन के आर्थिक संकट में निवेशक यहां पैसा लगाने से हतोत्साहित हो रहे हैं, जिससे चीन प्लस वन रणनीति को लागू करने की बाढ़ की जाती रही है, ताकि भारत एक आकर्षक निवेश स्थल बने। हालांकि, नीति आयोग का कहना है कि इसमें सीमित प्रोत्साहन मिली है। इसके अलावा, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया को अधिक लाभ हुआ क्योंकि वहां सरता श्रम, सरल कर कानून, कम शुल्क और तेज मुद्रा व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के लिए बेहतर यह हो

सकता है कि वह वैश्विक व्यापार में अपने स्थान को मजबूत करे, लेकिन नीकरशाही, लालफीताशाही और भ्रष्टाचार इसके मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं। अनुसंधान और नवाचार की कमी, साथ ही एफटीए समझौतों में असफलता, भारत को अन्य देशों की तरह सफलता दिलाने में विफल रही। जबकि अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर सख्त शुल्क लगा दिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन के विकास की तलाश कर में रही, लेकिन यह अवसर भारत में नहीं आ सका। इसके परिणामस्वरूप, व्यापार में श्रम सघन क्षेत्रों में भारती हिस्सेदारी घट गई और कृषि उत्पादों में प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ पाई। बासमती चावल का पेटेंट हमारे पास होने के बावजूद, पकिस्तान ने उसकी नकल कर ली। किसानों को निर्यात प्रोत्साहन नहीं मिल सका क्योंकि सरकार की अनुदान नीति के कारण अनाज की कीमतें बढ़ने लगी हैं। भारत अपने निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में प्रगति करने में अग्रणी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। उच्च लागत, गिरते मुद्रा मूल्य और सरत निर्यातों के कारण उत्पादकों को घाटा हो रहा है, जिससे नीति में कोई बदलाव नहीं आया। नीति आयोग ने चीन प्लस वन रणनीति की सीमित सफलता को स्वीकार किया है। हालांकि, पहले चीन में निवेश से बचकर व्यापार विविधता की आवश्यकता उभर चुकी है, भारत इस अवसर को अभी तक नहीं देख पाया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक ने भी कहा कि ट्रम्प की घोषणाएं भारत के लिए एक बड़ा अवसर हैं। अगर अब भारत खुद को सही तरीके से तैयार करता है, तो यहां

एक बड़ा आर्थिक उछाल आ सकता है, क्योंकि भारत का वैश्विक व्यापारिक चेहरा बदलने वाला है। अमेरिका, जो भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत की 'ग्लोबल फॉर लोकल' नीति की सराहना की है और यहां निवेश बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि, विदेश मंत्री एस. जयशंकर का कहना है कि सिर्फ निवेश बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, रूस को भारतीय उत्पादों के लिए अपने बाजार भी खोलने चाहिए। यदि निर्यात बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जाते हैं, तो बदलती स्थिति और भी आकर्षक बन सकती है।

पिछली तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट आई है, जबकि सरकार का बजट 2047 तक 7 प्रतिशत की विकास दर बनाए रखना है। इस गिरावट के कारण सरकार को सतर्क किया है कि वह अपने सार्वजनिक निवेश को घटाने के बजाय स्थिर बनाए रखे, क्योंकि यह पूंजी निर्माण में सहायक है। घरेलू निवेशकों द्वारा कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन विदेशी निवेशकों का समर्थन आवश्यक है, ताकि भारत चीन की जगह निवेश का आकर्षक स्थल बन सके। तभी भारत अपनी बेरोजगारी दर को कम कर सकेगा और मीडिया की मांग को पूरा कर सकेगा। इसके लिए व्यावस्थिकावाद पर्याप्त नहीं होगा, उसे कि मॉडर्न नीति में रैपिड रेट में कोई बदलाव न करने से स्पष्ट है। सरकार को साहसिक निर्णय और सही क्षेत्रों में समायोजी उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहिए।

—लेखक साहित्यकार हैं।

भागवत के बयान से उपजी उम्मीदें



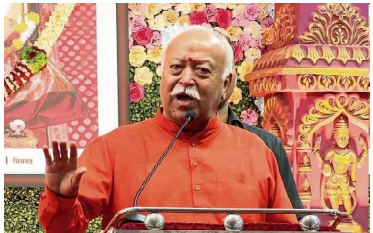
—ज्योति मल्होत्रा—

हाल में पुणे में संसंधन के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा की गयी टिप्पणी राहत का हवास करती है जिसमें सभी देशवासियों से मिलजुलकर रहने की जरूरत का आह्वान किया है। दिलचस्प उनकी ओर से सरकार को देश की विविध जातपूर्ण विषयों की याद दिलाना भी है। शायद उन्होंने महसूस किया कि एक समुदाय का बड़ा नेता बनने की होड़ वाली राजनीतिक सोच जरूरी है ही निर्मूल कर दी जाये।

अब जबकि यह सात खल होने को है, ऐसा कहना शायद अधिप्रायिक न होगी कि कई मायनों में 2024 आरएसएस प्रमुख मोहन मुबुकर राव भागवत का साल रहा। पुणे में बीते गुरुवार को संघ प्रमुख ने सहजीवन व्याख्यानमाला में 'भारतवृक्षगुरु' विषय वस्तु पर अपने संबोधन के दौरान जो नीतिगत टिप्पणियां की हैं, वे राहत प्रदान करने की दिशा में काफी चौकाने वाली लगती हैं।

उनका यह कहना कि 'मंदिर-मस्जिद विवाद अन्धवीर्यता' है और यह भी कि 'राम मंदिर के निर्माण के बाद, यदि कुछ लोग सोचने लगें हैं कि मुई-गुजराहों पर वे इस तरह के कूटनीतिक उपायों के नेता बन सकते हैं, तो यह कुतूहल नहीं है, आगे का है 'कोन अल्लस उद्यम है और कोन न बहुव्यक्ति और खुद ही इस सवाल का जवाब दिलाए: सभी समान हैं'।

कहा तो संविधान द्वारा एक 6 मंत्रिपरिषद् गणराज्य की गारंटी दिए जाने के 75 साल बाद, भागवत की टिप्पणियों को सामान्य माना जाना चाहिए था। लेकिन इसकी बजाय, इन्हें राहत की बात माना जा रहा है और जो सुर्खियों की भी। आरएसएस प्रमुख को अपनी ही सरकार को यह याद दिलाने में समय लग गया कि देश ऐसे लोगों से बना है जिनके विचार, परंपराएं, रीति-रिवाज, धर्म और भाषा एकदम अलगवादी हैं और अगर इस खिचबिच को अपना विशिष्ट स्वाद बनाए रखना है, तो शायद



इसे एक राष्ट्र-एक लोग के शिकड़े में जकड़ने के कोई मायने नहीं हैं। अनुमान के मुताबिक, राजनीतिक रूप से वामपंथी सोच वाले उनके पुणे भाषण में कोई न कोई कमी बूझने में लग गए दुकही अनुवाद में कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि भागवत ने अपना संबोधन मराठी में दिया था। इसी कयास से उलट, राजनीतिक रूप से दक्षिणपंथी भी शायद यह सोच रहे होंगे कि भागवत ऐसे एक पर रस्तम पर कौं भाषण ध्वज की डोर खींचकर उसे फहराने से परहेज कर रहे हैं, खासकर जब, जबकि मुसलमानों पर हिंजुक की जीत क्षितिज पर मंडरा रही है।

यह स्पष्ट नहीं है कि भागवत को केब बावत खड़ा गई और किस वजह से उन्होंने पुणे में यह टिप्पणी की। आखिरकार, आरएसएस की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए साल भर चलते-वाले समारोहों की शुरुआत के कुछ हफ्तों बाद, और क्रिसमस से कुछ दिन पहले (जिसे मोदी सरकार ने तुषासन दिवस घोषित कर रखा है, जो एक कार्यदिनांक भी है) उनका यह कहना कि हमें साथ रहना चाहिए? दु हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सभी को दु यह कथन अनोखा और दिलचस्प दोनों है।

कुछ हफ्ते पहले समर्थन मजिद के वास्तु के आधार पर इसमें मूल स्वरूप को लेकर समुदायों के बीच बड़बुझ के बाद पुलिस की गोलीबारी में पांच लोग की बेजबज मीत हो गई थी, लगता है इसके बाद से भागवत को अहसास हुआ है कि खुद को बेहतर हिंदू नेता सिद्ध करने वाली इस प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति को उध पकड़ने से पहले ही खत्म कर देना सही होगा।

शायद उन्होंने देख लिया है कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान, जो कि आबादी का 14 प्रतिशत है, उन्हें भी बाकी लोगों की तरह शांति और समानता से यही सनना है, और देश के एक अन्य विभाजन के बारे में

विचार भी सोच के दायरे से परे है। किसी और की तुलना में शायद उन्होंने करीब मंडरा रहे खराबों को पहचान लिया है। कदाचित उन्होंने अपने चारों ओर देखा और पाया कि कैसे दु और वया दु सीरिया, अफगानिस्तान और फिलिस्तीन जैसे इस्लामी राष्ट्र पिछले कुछ वर्षों में भरभरा कर डह गए। भारत के मुसलमान कई जात, जाति उनके आत्मसम्मान को कुछ लोग घोट पहुंचाने की कोशिश करे। बुलखोजर चलाने वाली तामची सोच पर भी सवाल उठे हैं।

आखिरकार, 2018 में भी भागवत ने दिल्ली में सवादादाताओं से कहा था कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। और पिछले साल, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पट्टी ने ज्ञानपीथ मस्जिद का संरक्षण करने की अनुमति दी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह कमी मंदिर था और टीवी पत्रकार इस निर्णय के निहितार्थों को लेकर हल्ला मचाने लगे, तो भागवत ने शांति से कहा, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग की तलाश क्यों करना?

निश्चित ही, यह बात कोई भी मानेगा कि आरएसएस प्रमुख और पीएम मोदी एक जैसे नहीं हैं। या फिर एक दशक में भाषणा के सत्ता में रहने से आरएसएस को बहुत लाभ नहीं हुआ है। बेशक, हुआ है। मोदी नहीं होते, तो अपोथ्या में राम मंदिर नहीं होता या दुनिया भर के 39 देशों में इसका विस्तार नहीं होता। आरएसएस प्रमुख के विचार इस बारे में स्पष्ट है कि सभी धर्मों के सभी भारतीय हिंदू हैं, क्योंकि एक समय में उनके पूर्वज भी हिंदू थे। अतुष्टार माह की शुरुआत में विचारधाराओं पर अपने संबोधन में भागवत ने स्पष्ट किया था कि उनके पास सदाकृतिमा एवं प्राकृतिक विचार और सदाकृतिमा एवं प्राकृतिक विचार एक समय नहीं है। उन्होंने कहा कि बालादेवी हिंदुओं को भारत से मदद की जरूरत है। लेकिनका 'द ट्रिब्यून' की प्रधान संपादक हैं।

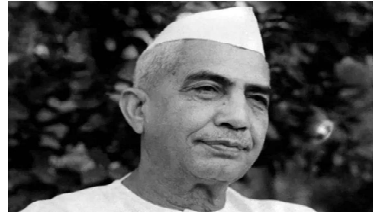
किसानों की बुलंद आवाज थे चौधरी चरण सिंह

—रमेश सराफ घमोरा—

देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक व्यक्ति नहीं विचारप्राप्त थे। चौधरी चरण सिंह ने हमेशा यह साबित करने की कोशिश की थी कि किसानों को खुशहाल किए बिना देश का विकास नहीं हो सकता। उनकी नीति किसानों व गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की थी। वो कहते थे कि देश की समृद्धि का रस्ता गांवों के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। उन का कहना था कि भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। जिस देश के लोग भ्रष्ट होंगे वो देश कभी तबकी नहीं कर सकता। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसम्बर 1902 को गाजियाबाद जिले के गुरूपर गांव के चौधरी मीर सिंह के घर हुआ था। बाद में उनका परिवार गुरूपर से जानी खुर्द गांव आकर बस गया था। 1928 में चौधरी चरण सिंह ने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा लेकर गाजियाबाद में वकालत प्रारम्भ की। 1930 में महाना गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने के समर्थन में चरण सिंह ने हिंजुन नदी पर नमक बाजार जित पर उन्हे 6 माह जेल की सजा हुई। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी चरण सिंह हिस्साकर किये गये। 1942 में अगस्त क्रान्ति के माहौल में चरण सिंह को गिरफ्तार कर डेढ़ वर्ष की सजा हुई। जेल में ही चौधरी चरण सिंह की लिखित पुस्तक शिष्टाचार भारतीय समाज में शिष्टाचार के नियमों का एक बहुमूल्य दस्तावेज है।

चौधरी चरण सिंह खुद एक छोटे से गांव में एक किसान के घर जन्मे थे। बचपन से ही उन्होंने गांव के किसानों, गरीबों के दुख-दर्द को नजदीकी से देखा जाना था। इसलिए उन्हें उनकी समस्याओं का बखूबी अहसास था। उनको जब कभी कहीं मौका मिलता वे गांव के किसानों की सच करने से नहीं बचते थे। उनके दिल में हमेशा गांव के किसान ही बसे रहते थे। चौधरी चरण सिंह जिसे जीवन पर्यंत गांधी टीपी बाणन कर महाना गांधी के सच्चे अनुयायी बने रहे।

उन्होंने किसानों की खुशहाली के लिए खेती पर बला दी थी। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके इसके लिए भी वो बहुत गहन रहते थे। उनका कहना था कि भारत का समूर्ण विकास तभी होगा जब किसान, मजदूर, गरीब सभी खुशहाल होंगे। चौधरी चरण सिंह की गिनती हमेशा एक ईमानदार राजनेता के तौर पर की जाती है। उन्होंने जीवन पर्यंत किसानों की



सेवा को ही अपना धर्म माना और अपने अंतिम समय तक देश के गांव में रहने वाले किसानों, गरीबों, दलितों, पीड़ितों की सेवा में ही पूरी जिंदगी गुजारी। चौधरी चरण सिंह जितने प्रथा के कट्टर खिलाफ थे।

आज देश के किसान कर्ज में डूबे हुये हैं। उनको उनकी उपज का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते देश में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। केन्द्र व राज्य सरकारें भी किसानों के भले की योजनाएं बना पाते हैं नकाम रही है। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां किसानों को झ्राना देकर उनके वोट चुराते लेती हैं। फिर किसी का ध्यान किसानों की समस्याओं के समाधान करने की तरफ नहीं जाता है। ऐसे में आज देश के किसानों को चौधरी चरणसिंह जैसे सच्चे किसान हितैषी नेता की जरूरत है। उनसे उनके हक में खड़ा होकर किसानों की आवाज बुलन्द कर सके व उनका वाजिब हक दिला सके। चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति में एक बड़े नेता थे। मगर इंदिरा गांधी के सहयोग से कुछ समय के लिये देश के प्रधानमंत्री बन कर उन्होंने देश में पहली बार कांग्रेस के खिलाफ बने एक मजबूत गठबंधन को तोड़ा था। उससे उनकी प्रतिष्ठा को भी गहरा आघात पहुंचा था।

चौधरी चरण सिंह को 1951 में उत्तर प्रदेश सरकार में न्याय एवं सूचना विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 1952 में डॉक्टर समुप्रार्नद के मुखमंत्रिपरिषद् काल में उन्हें राजस्व तथा कृषि विभाग का वाय्यिभक्त था। एक जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश में उनके बदीलत मंत्रीदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को खेती करने के अधिकार मिले। 1954 में उन्होंने किसानों के हित में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। चरण सिंह स्वभाव से भी कृषक थे तथा कृषक हितों के लिये अवरुध प्रयास करते रहे। 1960 में चंद्रभानु गुप्ता की सरकार में उन ही देश को आगे ले जा सकता है।

यह तथा कृषि मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश के किसान चरण सिंह को अपना रहनुमा मानते थे। उन्होंने कृषकों के कल्याण के लिए काफी कार्य किए। लोगों के लिए व एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके भाषण को सुनने के लिये उनकी जनकभाओं में भारी भीड़ जुट करती थी।

किसानों में चौधरी साहब के नाम से मशहूर चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तब 1967 में पूरे देश में साम्प्रदायिक अंधे होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में कहीं पता भी नहीं हिल पाया था। 17 फरवरी 1970 को वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अपने सिद्धांतों से उन्होंने किसानों की समझौता नहीं किया। 1977 में चुनाव के बाद जब सरकार में जनता पार्टी देश में आई तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चरण सिंह को देश का गृह मंत्री बनाया गया। केन्द्र में गृहमंत्री बनने पर उन्होंने अत्यवसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वे उत्तर प्रधानमंत्री बने। बाद में मोरारजी देसाई और चरण सिंह के मतभेद हो गये। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक चौधरी चरण सिंह साम्प्रदायिक पार्टियों तथा कांग्रेस के सहयोग से भारत के पांचवें प्रधानमंत्री बने।

चौधरी चरण सिंह एक कुशल लेखक भी थे। उनका अंग्रेजी भाषा पर अच्छा अधिकार था। उन्होंने कई पुस्तकों का लेखन भी किया। 29 मई 1987 को 84 वर्ष की उम्र में जब उनका इस्लान हुआ तो देश के किसानों ने सरकार में वरीरी करने वाला अपना नेता खो दिया था। लोगों का मानना था कि चरण सिंह से राजनीतिक कलितियां हो सकती हैं लेकिन वास्तिकता यह उभरती है कि उन्हें गलती नहीं की। इतिहास में उनका नाम प्रधानमंत्री से ज्यादा एक किसान नेता के रूप में जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह ने ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सच्चे पहले आवाज बुलन्द करते हुये आवाहन किया था कि भ्रष्टाचार का अन्त ही देश को आगे ले जा सकता है।

